(ख) सरकार को संसद सदस्यों से कितने अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ग) उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं और सभापटल पर रख दी जायेगी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमें

3182. श्री ईश दत्त यादव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्रमश: पांच, दस और पंद्रह वर्ष से अधिक समय से लंबित मुकदमों की संख्या कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान ऐसे मुकदमों के निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सरकार इन लंबित मुकदमों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और इसे यथासंभव शीघ्र निपटाने के लिए तरीकों और उपायों का पता लगाने के लिए मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक 4 दिसंबर, 1993 को हुई थी जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री जी ने की थी। सम्मेलन में अंगीकृत किए गए विभिन्न संकल्पों को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र, प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को जिनमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी सम्मिलित है, आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

मामलों के शीघ्र निपटाए जाने के मार्ग में आने वाली अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से, न्याय प्रशासन को एक योजना मद बनाया गया है।

Unethical practices by Subordinate Courts

3183. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the news-item captioned caught in a cobweb of delays which appeared in the 'Hindustan Times' dated the 14th July, 1994;

(b) if so, the facts thereof and the reaction of Government thereto;

(c) whether the judges in the lower courts adjourn the hearing of the cases frequently on unsound grounds as a matter of routine;

(d) if so, the steps taken to lay down guidelines to grant adjournments by the lower courts;

(e) whether lower courts in Delhi are granting ex-parte injunctions to parties as a matter of routine to the discomfiture of the other party;

(f) if so, the steps taken to a check the abuse of the authority in the lower courts;

(g) the details of judges of subordinate courts in Delhi found indulging in unethical practices; and

(h) the action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) and (b) Yes, Sir. Keeping in view, the problem of arrears of cases in courts and in order to find out ways and means to deal with it as expeditiously as possible, a meeting of the Chief Ministers and Chief Justices of High Courts was held on the 4th of December, 1993 under the chairmanship of the Prime Minister. The resolution adopted in the Conference have been commended to all the State Governments/UT Administration and High Courts for necessary action. Additionally, the Administration of Justice has been made a Plan item, with a view to remove infrastructural bottlenecks coming in the way of expeditious disposal of cases.

(c) and (d) No, Sir. Guidelines for granting of adjournments are provided in the Code of Civil Procedure and in the Delhi High Court Rules and Orders. Moreover, grant of adjournments is a matter that lies in the judicial discretion of the court keeping in view the interests of justice and the facts and circumstances of the case.